Price Decontrolled Drugs:

1.	Folic Acid	2631.62	3241 04
2.	Niacinamide I.P.	157.00	190·00
3.	Sulphaquanidine I.P.	142.50	177·00
4.	Vitamin B-1 Hcl (Oral Grade)	950.00	1132.00
5.	Vitamin B-1 Hcl (Amp. Grade)	1005.00	1176·00
6.	Vitamin B-1 (Mono)	1011.50	1228.00
7.	Vitamin B-2	2098.00	2384.00
8.	Vitamin B-6	1200.00	1571.00

भाखड़ा बांध का जल स्तर

*@334. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :***

श्री राम जेठमलानी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांध के निर्माताओं की राय के अनुसार, पंजाब स्थित भाखड़ा बांध के जलाशय में कितना जल स्तर निश्चित किया गया था ;

(ख) क्या गत वर्ष इस बांध के जलाशय में पानी का उक्त स्तर कायम रखा गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि सितम्बर, 1988 के महीने में बांध के जलाशय में पानी का स्तर पिछले वर्ष के जल स्तर की अपेक्षा कुछ अधिक ऊंचाई पर रखा गया था; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि बरसात के कारण, सितम्बर, 1988 में जनता को कोई पूर्व चेतावनी दिये बिना उक्त बांध से पानी छोड़ दिया गया था जिसके फलस्वरूप बाढ़ ने भयावह रूप धारण कर लिया ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्रचालन, अनुरक्षण तथा प्रेक्षण हेतु अभिकल्पकों (डिजाइनर्स) से संबंधित मापदण्ड, खण्ड-एक-गोबिन्द सागर के अनुसार, गोबिन्द सागर (भाखड़ा जलाशय) का अधिकतम स्टोरेज स्तर, औसत समुद्र स्तर से उन्नतांश (एलीवेशन)–1690 (515.11 मीटर) पर होना चाहिए बशर्ते निर्धारित किए अनुसार, बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापित की गई हो । बाढ़ संबंधी पूर्व सूचना प्रणाली 1965 में स्थापित की गई थी और तब से यह ठीक प्रकार से कार्य कर रही है ।

(ख) से (घ) वर्ष 1987 के दौरान सूखे की परिस्थितियों के कारण भाखड़ा में अधिकतम जल-स्तर 23–9–1987 को औसत समुद्र स्तर से 1666.21 फुट अधिक था, जोकि स्वीकृत अधिकतम जलाशय स्तर से काफी कम था । 1988 में जलाशय स्तर अपेक्षाकृत अधिक था परन्तु निर्धारित अधिकतम स्टोरेज स्तर से कम था और दिनांक 13–9–1988 को यह 1687.55 फुट था ।

(ङ) जी, नहीं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भाखड़ा बांध से पानी छोड़े

@पूर्वतः तारांकित प्रश्न 254, 29 नवम्बर, 1988 से स्थानांतरित ।

जाने के बारे में जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित प्राधिकारियों को यथासमय सूचित कर दिया गया था ।

Promotional Avenues of Extra Departmental Employees

*335. SHRI ASHWANI KUMAR:
SHRI LAL K. ADVANI:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the promotional avenues for Extra Departmental employees; if so, what are the details thereof;

(b) the number of Extra Departmental employees promoted to Group 'D' posts and to the cadre of Postmen during each of the last three years and so far during the current year; and

(c) the total number of ED employees in the country as at present?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BIR BAHADUR SINGH): (a) No, Sir.

(b) The information is as under:—

Group 'D'

1985	*1986*	*1987*	*Up to August, 1988*
421	328	1997	956

Postman

1985	*1986*	*1987*	*Up to August, 1988*
442	471	2062	727

(c) Total number of E.D. Employees in the country at present is about 2,98,000.

Development of Hydro-electric power Potential

*336. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the National Hydro-Electric Power Corporation has proposed a new time frame for the accelerated development of hydro-electric power potential in the country;

(b) if so, whether this stand was taken to make the hydro-electric projects competitive with the thermal power stations;

(c) whether the existing time frame of 15 years will be reduced to about 9.5 years; and

(d) if so, whether this will be possible if the latest method of investigation and construction and timely action for various clearances including forest and environment are adopted; if so, what measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI KALPNATH RAI): (a) to (d) For reducing the gestation period of hydro-electric projects, National Hydro-electric Power Corporation Ltd., had, *inter alia*, suggested acceptance of the concept of two-stage clearance of hydro-electric projects for investment decision, namely, the pre-construction works and the main project works. Government have accepted the suggestion, in principle, in respect of Central Sector and Joint veture (between Central Government and one or more State) Hydro-electric projects. Sanction for the pre-construction works of Uri Hydro-electric Project has already been accorded under this Policy.